

विचार बिन्दु

धैर्य कडुवा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। —रूसो

राजस्थान : श्री अन्न उत्पादन में सिरमौर - उज्ज्वल भविष्य

राजस्थान सहित भारत में मोटे अनाज, जिन्हें श्री अन्न के रूप में जाना जाता है, ने हाल के वर्षों में अपनी पोषण शक्ति, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक संभावनाओं के कारण वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। 2024–25 में भारत ने 180.15 लाख टन मिलेट का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। इस उत्पादन में राजस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने न केवल देश में बल्कि वैश्विक मिलेट उत्पादन में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) 2023 के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 38.4% हिस्सा देता है। राजस्थान, अपनी अनुकूल जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक खेती की प्रथाओं के साथ, इस क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। राजस्थान में श्री अन्न के उत्पादन, इसके स्वास्थ्य लाभ, जैविक खेती, पर्यावरणीय अनुकूलता, पशु आहार में उपयोग, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, नवीन खाद्य उत्पादों, युवा पीढ़ी के उत्साह, सरकारी सहयता, कम लागत उत्पादन और निर्यात में अग्रणी इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय और अर्ध-शुष्क जलवायु मिलेट की खेती के लिए आदर्श है। बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज इस क्षेत्र में सदियों से उगाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये कम पानी और न्यूनतम उर्वरकों की आवश्यकता के साथ कठिन परिस्थितियों में पनप सकते हैं। बाजरा, जो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित मिलेट है, न केवल स्थानीय आहार का हिस्सा है, बल्कि यह पशु आहार और जैविक खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2024–25 में राजस्थान ने देश के कुल मिलेट उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसमें बाजरा का हिस्सा सर्वाधिक रहा। यह उपलब्धि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राज्य की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का समन्वय है।

मिलेट का सबसे बड़ा लाभ इसका पोषण मूल्य है। ये अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन (विशेष रूप से बी-कॉम्प्लेक्स) और खनिजों जैसे लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ग्लूटेन-मुक्त होने के कारण ये सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त हैं, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हैं। राजस्थान में, जहां कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है, मिलेट ने स्थानीय आहार में पोषण की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4, 2015–16) के अनुसार, राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के 39.1% बच्चे कद में छोटे थे, और 46.8% महिलाएं एनीमिया से प्रस्त थी। इस श्री अन्न ने अर्थात मिलेट, विशेष रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का, आयरन और कैल्शियम की पूर्ति में सहायक हैं, जिससे कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है। राजस्थान सरकार ने आंगणवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिलेट आधारित भोजन को शामिल किया है, जैसे बाजरे की विचड्डी और रागी के लड्डू, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन के रूप में परोसे जाते हैं।

मिलेट की खेती पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। ये फसलें कम पानी और उर्वरकों पर निर्भर होती हैं, जिससे यह रासायनिक खेती के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करती है। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की हैं। 'राज किसान जैविक' मोबाइल ऐप, जैविक हाट (सुगंपुरा, जयपुर), और जैविक आदान (डूम, बाल्दी, आदि) पर 50–75% सब्सिडी जैसी योजनाएं किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जैविक खेती न केवल मिट्टी को उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी मदद करती है। मिलेट की फसलें सूखा-सहिष्णु होती हैं और उच्च तापमान में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जो राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक खेती के तहत नीति आयोग की पहल में राजस्थान में 17,900 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, और 13,946 किसानों को जैविक खेती के लिए उपकरण प्रदान किए गए हैं।

मिलेट का उपयोग केवल मानव आहार तक सीमित नहीं है, यह पशु आहार के रूप में भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान, जो देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पशुपालन के लिए मिलेट के अवशेषों और चारे पर निर्भर है। मक्का,बाजरे और ज्वार के डंठल पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करते हैं, जिससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जैसलमेर जिले में प्रति व्यक्ति 1,085 ग्राम दुग्ध की उपलब्धता इस बात का प्रमाण है कि पशुपालन और मिलेट उत्पादन का गहरा संबंध है। इसका सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान है, क्योंकि पशुपालन

मिलेट का सबसे बड़ा लाभ इसका पोषण

मूल्य है। ये अनाज प्रोटीन, फाइबर,

विटामिन (विशेष रूप से बी-कॉम्प्लेक्स)

और खनिजों जैसे लोहा, कैल्शियम और

मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ग्लूटेन-

मुक्त होने के कारण ये सीलिएक रोग से

पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त हैं, और कम

ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह

रोगियों के लिए लाभकारी हैं।

(एफपीओ) को मिलेट प्रसंस्करण और विपणन में शामिल किया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। मिलेट आधारित नवीन खाद्य पदार्थों ने राजस्थान में खाद्य उद्योग को नई दिशा दी है। बाजरे के बिक्रित, रागी के नूडल्स, मक्का और ज्वार की खिचडी, और मिलेट आधारित स्नैक्स जैसे उत्पादों ने शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में लोकप्रियता हासिल की है। स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों ने मिलेट को आधुनिक उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार पुनर्जनन किया है। उदाहरण के लिए, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों में मिलेट कैफे और रेस्तरां खुल रहे हैं, जो पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का मिश्रण पेश करते हैं। यह नवाचार न केवल खाद्य संस्कृति को समृद्ध कर रहा है, बल्कि स्थानीय किसानों को भी बाजार से जोड़ रहा है।

युवा पीढ़ी में मिलेट की लेकर उत्साह बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मस के माध्यम से, युवा उद्यमी और किसान मिलेट के लाभों को बढ़ावा दे रहे हैं। 'मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर' जैसे पहल, जो दिल्ली हाट में स्थापित किया गया है, ने राजस्थान के युवाओं को प्रेरित किया है कि वे मिलेट आधारित व्यवसाय शुरू करें। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफपीओ गठन ने युवा किसानों को मिलेट की खेती और विपणन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों में मिलेट पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष पद्धतःकम शुरू किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की सहयता ने मिलेट उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) के तहत राजस्थान में मिलेट की खेती के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-एफएमई योजना के तहत 2,000 करोड़ और उत्पाद-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 800 करोड़ का निवेश मिलेट प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए किया गया है। राजस्थान सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया है, जिसमें मिलेट उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान हैं। 'राज किसान जैविक' ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों ने किसानों को जैविक मिलेट के क्रेता-विक्रेता से जोड़ा है, जिससे उनकी पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ी है। मोटे अनाज के निर्यात के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2024–25 में भारत ने 89,164.96 टन मिलेट का निर्यात किया, जिसमें राजस्थान का योगदान प्रमुख रहा। मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मिलेट की मांग मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ रही है। एपीडी के नेतृत्व में निर्यात संबंधित मंच और मिलेट निर्यातक पोर्टल ने राजस्थानी किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। निर्यात से होने वाली आय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और किसानों की आय में 20–30% की वृद्धि रज्व की गई है।

हालांकि, मिलेट उत्पादन और विपणन में कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है जागरूकता की कमी। शहरी उपभोक्तार्ओं में मिलेट के पोषण लाभों के बारे में जागरूकी का अभाव है, जिसके कारण इसकी मांग अभी भी सीमित है। दूसरी चुनौती है प्रसंस्करण और भंडारण की कमी। मिलेट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। तीसरी चुनौती है वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा। अन्य देश, जैसे अफ्रीका और यूरोप, भी मिलेट निर्यात में सक्रिय हैं, जिससे भारत को गुणवत्ता और कीमत में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उच्च उपज वाली किस्मों और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच सीमित है, जिसे दूर करने के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, राजस्थान में मिलेट का भविष्य उज्ज्वल है। सरकार, किसान, और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों ने श्री अन्न को एक टिकाऊ और लाभकारी फसल के रूप में स्थापित किया है। मिलेट न केवल पोषण और स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-आर्थिक विकास, और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। राजस्थान, अपनी पारंपरिक खेती की विरासत और आधुनिक नवाचारों के साथ, इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां, युवा पीढ़ी का उत्साह, और वैश्विक मांग का बढ़ता रझान मिलकर श्री अन्न को एक नई पहचान दे रहे हैं, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है।

—अतिथि संपादक,

राजेन्द्र मोहन शर्मा

वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद् और चिन्तक



महावीर सिंह

शहरों में बहुत सी पॉपुलर चाय, पान की दुकानें, थडिया, प्रातः टहलने वालों के समूह, गांवों में पीपल – बड़ के गट्टों पर बैठे ताशपती खिलने वालों के समूह देश-विदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते मिल जाऐंगे। ऐसे मुद्दों पर लोगों की राय जानने के बेहतरीन अवसर प्रदान करते है। इन्ही समूहों में चली चर्चाओं, बहसों के कुछ अंश इस लेख में दिए जा रहे है:—

आजकल आए दिन कोई न कोई बाबा, मौलवी, धर्माधिकारी, कथावाचक, --- बहन, बेटियों, बीवियों के पहनावे, चरित्र पर तरह-तरह से ज्ञानवृद्धि कर रहे है। ऐसी ऐसी बातें कहीं है जिन्हें यहां लिखना पढ़ने वालों की तोहीन होगी।इन कथावाचकों, मौलवियों, तरह-तरह के सिद्ध आचार्यों आदि की जबान को आशाराम, राम रहीम और न जाने ऐसे कितनों के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले लकवा क्यो मार जाता है? इन आशा रामों, राम रहीमों को कितनी आसानी से जमानत, दर्जनों बां पेरौल मिल जाता है!!!?? एक आदमी को तो, चुनाव आए नहीं, उसका जन्मदिन आया नहीं, झूट पेरौल मिल जाती है। क्या जरबरस्ट सेटिंग-वेटिंग है सेटिंग की सरकारों से।

क्या इन्होंने जो बहुचर्चित कारनामों किए है, उनमें, इन सत्ता में बैठे बड़े लोगों की भी किसी किसी प्रकार से भागीदारी होती है क्या? यह आम आदमी पूछता रहता है। हम हिन्दू भाई मंदिर में भी बाहुबल दिखाने से नहीं चुकते। किसी वार-त्यौहार पर मंदिर जाए। बिना धक्का-मुक्की के दर्शन कर लें तो ही समझो कि, शायद, भगवान जो आप पर बहुत ही मेहरबान है। भगवान के दर्शन के लिए इतनी धक्कम-धक्की, लगता है, हम हिन्दुओं का इस काम पर एकाधिकार है। एक सज्जन का कहना था कि इतनी कठिनाइयों के बीच जो श्रद्धालु दर्शन किए बिना नहीं जाते तो भगवान जो का कोमल हृदय तो उन पर पिघलेगा, आशीर्वाद, मनचाहा वरदान देगा ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा मैया। कम लिखने में कोई प्रोटोकॉल संबंधी गलती हो तो इस

संस्थाओं को समय-समय पर नये

कदम उठाने और नवाचार करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण ऐसी ही एक पहल है।

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने की पहल की कि मतदाता सूची में केवल वैध मतदाता ही शामिल हों।

यह कदम इस बात को दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक पूर्णतः स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो सरकार से पूरी तरह अलग होकर कार्य करती है। इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले वर्षों में बार-बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई

नादान को माफ करते हुए, आप ही, शांति से, सुधार कर लेना।

वैसे यों ही, चलते-चलते एक बात कह दी किसी ने की चर्चों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दर्शनों के लिए इतनी धक्का-मुक्की क्यो नहीं होती??? कुछ सू्रमा आए दिन फतवा जारी करते रहते है कि कब-कब क्या क्या नहीं खाना। इस बार किसी बड़े सूबे की सरकार ने उनकी बात सुन ली। एक पुराना, विस्मृत आदेश निकाल कर फतवा जारी कर ही दिया कि 15 अगस्त, आजादी के दिन मांस-मच्ची सेवन निषेध। आजादी के दिन खाने-पीने की आजादी खत्म। कर लो क्या करोगे?

न्यायालयों के भी कुछ फैसले जन चर्चा के मुद्दे बनते ही रहते है। कबूतर खाने कहां होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो कहां-कहां? इसका फैसला भी उच्च या उच्चतम न्यायालय ही करे और वह भी धार्मिक और पक्षी प्रेमी संगठनों से पूछ के करे? तो फिर यह नगर निगम या उनसे उपर बैठी सरकार करती है? चर्चाओं में सुन --- करते है न, विज्ञापनों के माध्यम से नेताओं के चिकने-चुपड़े चेहरों के बड़े अखबारों, टीवी चैनल्स पर दिखाए और उनके द्वारा स्वर्ग जैसा हिंदुस्तान बना देने की शेखी बघारने को सुनाते रहना।

दिल्ली में कुर्तों के संबंध में भी कोई निर्णय हुआ। इन्हें शेल्टर होम भेजने के निर्देश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और पशु प्रेमी, राजनता लोग हो गए आक्रोशित, आंदोलित?? वैसे, अगर, सड़कों पर लोग कुत्ता प्रेम दिखाते हुए, बिरिकट्स खिलते हुए दिखें और दूसरा कोई ऑब्जेक्शन करे तो उसे क्या सुनना पड़ सकता है, कोई अंदाज है --- सबसे कॉमन है,अबे चल अपना काम कर, खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को तो करने दे, इन निरहि प्राणियों की सेवा ---। वैसे कुत्ते भी फाइव स्टार फूड के अन्धस्त हो गए, ऐसे वैसी बिरिकट्स, पुरानी बासी रोटी – सब्जी आदि की तरफ आंख भी नहीं उठते!!! फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ, अवमानना की कार्यवाही होगी क्या? खबर तो छापी है, हांय या पर क्या पता, नहीं भी हो ??? आदेश तो है, किसी इलाके में आवारा कुत्ता घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए – --(आंकोंड पर नजर डालें, बड़े भयावह है -- 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट, 54 लोगों की डेथ, रोजाना 10 हजार से अधिक काटने के केसेज!!!!) फिर भी स्थानीय, प्रदेशीय और केंद्रीय सरकारी नहीं जागें तो क्या करेगा कोर्ट, फिर चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, क्या फर्क पड़ेगा मुदे?

इतिहास से गुड़ते हुए निकाल कर लड़ना, हमारा पसंदीदा खेल है। कई बोलने वाले शूरवीर अखंड भारत की

सीमाओं के अनुसार अखंड देश बनाने के जोशीले भावण हमेशा देते रहते है। कौन सा अखंड भारत कौन सी सीमाएं यह मत पुछ लेना। ज्यादा कोई पूछे तो अखंड भारत माता का एक कालजई चित्र है, राजा रवि वर्मा का उसकी सीमाएं बता देते है। इस से गहरे इतिहास ज्ञान को न उनको जरूरत और न उनके तय श्रोताओं को। भूतकाल पर गर्व करते रहना – उस में ही आत्म मुग्ध रहना हमें स्वर्ग में रहने जैसा सुख देता है। भूत कल में हम परमाणु बम, सबसे आधुनिक मिसाइल, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मानव रोग निदान के वर्तमान में ज्ञात सारे उपचार – सर्जरी का जाए प्राप्त कर चुके थे आदि आदि। अत्याधुनिक हथियार बनाना हमारे पूर्वजों का बाएं हाथ का खेल था। यह जो ब्रहोस, तेजस, अग्नि आदि पर जो गर्व करते है न, वो सब पहले से ही हमारे, देव रचित धर्म शास्त्रों में वर्णित है। थो कुछ अक्ल के दुश्मन या उनसे उपर बैठी सरकार करती है? फिए ऐसा क्या हुआ कि इन सिकंदर, हनु, कुषाण, शक, मुसलमान, मुगल, अंग्रेज – आदि ने हमारे अखंड भारत की सीमाएं पर कैसे की???

एक तो ऐसे शूरवीर हैं जो अब भी,आजादी के 78 साल बाद भी यह कहते नहीं अघाते कि गुलामी के सारे अंश मिटा कर मानेंगे। एक ने धीरे से पूछा कितनी कब्रें और खोदनी है, कितने मस्जिद, चर्च आदि वहाने है। कइयों को इनके नींचे भी मंदिरों के होने के सपने तो आते रहते हैं!!! वैसे हमारा इतिहास इस प्रकार के मुद्दों से भरा पड़ा है। सदियों तक, नेताओं, तथाकथित सांस्कृतिक संगठनों को मसाला – काम मिल सकता है -- खोदा फाट्टा है -- कौन्ने-कौन्ने के लिए वैसे शुक्र है अभी अंग्रेजों की बनाई इमारतों, चर्चों, शिक्षण व चिकित्सा संस्थानो पर इन शूरवीरों की नजर नहीं पड़ी। वैसे वर्तमान में इतिहास पुनर्लेखन, संस्कृतिकरण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। जल्दी ही विदेशियों के पिछलगुओं द्वारा लिखे इतिहास से मुक्ति मिल जाएगी। हल्दीवादी युद्ध में महारणा प्रताप को विजयी घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं। खानवा युद्ध में भी बाबर की विजय के स्थान, कम से कम, युद्ध को अनिर्णत तो दिखाया ही जा सकता है। इब्राहिम को, इस युद्ध के अनर्णय का दोषी तो ठहराया ही जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरे तथ्यों का शुद्धिकरण कर, गलत तथ्यों को हटा दिया जाएगा। सभी मंत्री, सहलाकर, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

और जिज्ञा ने यह किया, कुछ का कहना है वीर सावरकर, हिंदू महा सभा, जिज्ञा ने यह किया। आने वाले दिनों में सड़कों पर इसका भी फैसला हो ही जाएगा। वैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार, जिज्ञा व हिन्दू महासभा, मुख्य रूप से जिम्मेदार थ। ऐतिहासिक व भौगोलिक दृष्टि से यह, उस समय की, धरातलीय सच्चाई का मूर्त रूप था।

ऐसे समूहों में संविधान पर बात न हो ऐसा ही नहीं सकता। देखते ही देखते, इम्तीनान से चाय की चुस्कियां लेने वाले दो समूहों में बंट गए। एक का कहना था भारत का संविधान में किसान, मजदूर, व्यापारी, व्यवसाई, एस सी, एस टी, ओबीसी,सभी भाषा बोलने वालों, सब को उन्नति के अवसर देता है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, राज कार्य में धर्म आधार पर निर्णय नहीं होकर संविधान के अनुसार कम होता है। एक व्यक्ति एक मत,अब को समान अधिकार। कानून अब के लिए बराबर दूसरे पक्ष का कहना था कि इसमें भारतीय समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शास्त्रीय मूल्यों का सर्वथा अभाव, पूर्णतः भारतीयता विहीन।

जन्म कुंडली देख कर इलाज का पवित्र कार्य तो वर्षों पहले से चल रहा है। अब तो अपराधियों की जन्म से, उनकी पूरी अपराध कुंडल खोज जाएगी और भविष्य में उनको क्या क्या अपराध करने है इन सब बातों का पता चल जाएगा। समाज पूर्णतः अपराध मुक्त!! जो काम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भी लाख कोशिश करके नहीं कर पाए, वो आम होगा। फिर इतनी पुलिस की क्या जरूरत रहे जाएगा??

जन्माष्टमी का शुभ दिन था। एक प्रातः भ्रमणकारी भाई ने दूसरे से कहा, जय श्री कृष्ण ---- दूसरे ने बुलंद आवाज में कहा, जय जय श्री राम बोलो पहले फिर जय कृष्ण। तीसरा दूर से ही बोला श्रीराम, श्रीकृष्ण दोनों गंगा मैया की देन है और गंगा मैया को धरती पर लाए जय बम भोले, सो, सबसे पहले बोलो जय श्री बंब भोले, जय श्री बंब भोले, जय श्री बंब भोले, आधे घंटे चली। बीच में एक बंगाली बाबू भी कुदे। सब की मैया जय काली मैया, बुबो दे दुश्मन की नैया। मैया नहीं तो कोई नहीं, सबसे बड़ो है मैया।

जन्माष्टमी पर गौ माता के बारे में बात न हो तो, ठीक नहीं। कुछ सिरफिरे पूछते है कि यह गोरक्षक छोटे मोटे व्यापारी,चरवाहों पर शौर्य प्रदर्शन करते है, क्यो नहीं बूचड़खानों पर धावा बोल, एक झटके में पूरा कर देते यह रोज रोज का झंझटा वैसे एक आदमी में बनाया कि गोरक्षकों की चौकियां बनी हुई है, ऐसे से आगे दूसरे को सूचना पहुंचती

विशेष गहन पुनरीक्षण : जनता की सेवा में

संस्थाओं को समय-समय पर नये कदम उठाने और नवाचार करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण ऐसी ही एक पहल है।

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने की पहल की कि मतदाता सूची में केवल वैध मतदाता ही शामिल हों।

यह कदम इस बात को दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक पूर्णतः स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो सरकार से पूरी तरह अलग होकर कार्य करती है। इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले वर्षों में बार-बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

रोजमर्रा के निर्णयों में जवाबदेह है। इसके फैसलों को केवल न्यायपालिका के समक्ष, चुनाव याचिका या संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत दाखल रिट द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। यही स्वतंत्रता आयोग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है और लोकतांत्रिक विहार जैसे राज्य के लिए, जहां पिछली बार ऐसा बड़ा संशोधन 2003 में हुआ था, यह अद्यतन काफी देर से हो रहा है।

यह रेखांकित करना भी आवश्यक है कि इस संबंध में आयोग के फैसलों की कोई जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर नहीं आती। विपक्ष द्वारा बार-बार केंद्र और आयोग के निर्णयों को जोड़कर देखने की कोशिश संविधान की संरचना के विपरीत है। चुनाव आयोग न तो संसद के प्रति और न ही कार्यपालिका के प्रति अपने

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैटिव्ड उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते है कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू

हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की प